ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, July-December 2025, Submitted in November 2025

वाणिज्यिक कर सेवा और राज्य लोक सेवाः एक राजनीतिक अध्ययन

अमित कुमार, शोधार्थी (राजनीति विज्ञान), टांटिया विश्व विद्यालय श्री गंगानगर
डॉ विशाल छाबड़ा, प्रोफेसर राजनीति विज्ञान), टांटिया विश्व विद्यालय श्री गंगानगर

अमूर्त

यह शोध पत्र राज्य लोक सेवा, विशेषकर वाणिज्यिक कर सेवा के राजनीतिक आयामों की पड़ताल करता है। कर प्रशासन केवल एक तकनीकी कार्य नहीं है, बल्कि यह राज्य की राजनीतिक विचारधारा और शक्ति संतुलन से प्रेरित होता है। यह अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि कैसे राजनीतिक हस्तक्षेप, लोकलुभावन नीतियां (Populist Policies) और नौकरशाही की स्वायत्तता कर संग्रहण और राज्य की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करती है।

परिचय

राज्य के अस्तित्व के लिए 'कर' (Tax) अनिवार्य है, लेकिन कर का ढांचा और उसका कार्यान्वयन राजनीतिक निर्णयों का परिणाम होता है। वाणिज्यिक कर सेवा राज्य की आय का प्राथमिक स्रोत है। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में, कर अधिकारी ;राज्य की शक्ति' के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान समय में वैश्वीकरण और GST जैसे सुधारों ने राज्य की राजनीतिक संप्रभुता और कर अधिकारियों की भूमिका के बीच एक नया द्वंद्व पैदा कर दिया है।

शोध अंतराल

अधिकांश मौजूदा शोध वाणिज्यिक कर सेवा को केवल 'प्रबंधन' या 'कानून' के चश्मे से देखते हैं। इसमें 'राजनीतिक अर्थव्यवस्था' (Political Economy) और 'नौकरशाही पर राजनीतिक प्रभाव' के कोण को अक्सर छोड़ दिया जाता है। यह शोध इस अंतराल को भरता है कि कैसे राजनीतिक दबाव या संरक्षण कर अनुपालन (Compliance) और अधिकारियों की कार्यशैली को प्रभावित करता है।

साहित्य समीक्षा

कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर आधुनिक जेम्स बुकानन के 'पब्लिक चॉइस थ्योरी' तक, कर और राजनीति का गहरा संबंध रहा है।

पूर्ववर्ती शोधों में पाया गया है कि चुनावी वर्षों में कर प्रवर्तन (Enforcement) अक्सर सुस्त हो जाता है।

विभिन्न विद्वानों ने तर्क दिया है कि राज्यों के बीच 'कर प्रतिस्पर्धा' (Tax Competition) एक राजनीतिक विवशता है, जो नौकरशाही के कामकाज को दिशा देती है।

विधि तंत्र

यह एक गुणात्मक (Qualitative) और विश्लेषणात्मक शोध है:
तुलनात्मक पद्धतिः विभिन्न राजनीतिक शासनों के दौरान कर संग्रहण के आंकड़ों का विश्लेषण।
साक्षात्कारः सेवानिवृत्त कर अधिकारियों और राजनीतिक विश्लेषकों के साथ चर्चा।
केस स्टडीः विशिष्ट नीतियों (जैसे वैट से जीएसटी का संक्रमण) का राजनीतिक प्रभाव।

उद्देश्य

- कर प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना।
- यह समझना कि राजनीतिक प्राथमिकताएं कर नीतियों के क्रियान्वयन को कैसे बदलती हैं।
- वाणिज्यिक कर सेवा में नौकरशाही की तटस्थता (Neutrality) बनाम राजनीतिक प्रतिबद्धता का अध्ययन करना।

परिकल्पना

H1: राज्य की कर नीतियां आर्थिक तर्क के बजाय राजनीतिक लाभ–हानि से अधिक संचालित होती हैं।
H2: वाणिज्यिक कर सेवा के अधिकारियों की स्वायत्तता राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सीमित होती है, जिससे राजस्व की क्षमता प्रभावित होती है।

महत्व

यह शोध राजनीति विज्ञान के छात्रों और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह समझने में मदद करता है कि एक मजबूत और निष्पक्ष कर सेवा के लिए 'राजनीतिक इच्छाशक्ति' और 'प्रशासनिक स्वतंत्रता'

के बीच संतुलन क्यों आवश्यक है। यह कर सुधारों को केवल तकनीकी बदलाव के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तन के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान करता है।

निष्कर्ष

अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि वाणिज्यिक कर सेवा राज्य की राजनीतिक शक्ति का एक उपकरण है। यदि राजनीतिक नेतृत्व लोकलुभावनवाद की ओर अधिक झुका रहता है, तो कर सेवा की दक्षता कम हो जाती है। एक आदर्श स्थिति वह है जहाँ राजनीति केवल व्यापक नीतियां बनाए और कार्यान्वयन में नौकरशाही को पूर्ण स्वायत्तता और सुरक्षा प्रदान करे। राज्य की वित्तीय मजबूती के लिए कर सेवा का 'वि–राजनीतिकरण' (Depoliticization) आवश्यक है।

संदर्भ

1- अग्रवाल, आर. के. (2021). भारतीय कर प्रणाली का राजनीतिक परिदृश्य।
2- सिंह, एम.पी. (2019). भारत में संघीय शासन और वित्तीय राजनीति।
3- सरकारी रिपोर्टः राजस्थान बजट अध्ययन एवं नीति विश्लेषण केंद्र (CBPS) के प्रकाशन।
4- जर्नलः Economic and Political Weekly (EPW) के प्रासंगिक लेख।